

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**INDEX**

IN

Reply/Response of

Uttarakhand Pollution Control Board

In the matter of

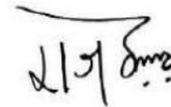
Original Application No. 417 of 2022

Niranjan Bagchi Vs State of Uttarakhand & Ors.

<b>S.No.</b>	<b>Description of Paper</b>	<b>Pg. No.</b>
1.	Index	1 – 1
2.	Compliance Affidavit	2 - 3
3.	Annexure-1: Minutes of Meeting held on dated 24.08.2023.	4 - 5
4.	Annexure-2: Copies of letters dated 20.11.2023 & 03.02.2024.	6 -
5.	Annexure-3: reply of Uttarakhand Peyjal Nigam dated 25.10.2023.	

Dated: February 5, 2024

Filed by:



Dr. Rajendra Singh  
Scientific Officer  
Uttarakhand Pollution Control Board  
Dehradun

**In the matter of OA No. 417/2022**

**Niranjan Bagchi Vs State of Uttarakhand & Ors.**

1. That the above noted Application was listed for hearing on 25.07.2023, wherein Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue following directions:- ".....

*17. Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MoEF & CC.*

*18. Accordingly, we direct the Secretary, Environment, Uttarakhand to re-examine the matter and to take appropriate action. We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/ river body and to ensure the compliances of the environmental act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks."*

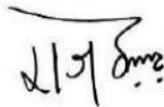
*....."*

2. That in compliance of above order of Hon'ble NGT, meeting was held on 24.08.2023 under the Chairmanship of Principal Secretary, Government of Uttarakhand. Copy of minutes of Meeting held on dated 24.08.2023 is enclosed as **Annexure-1**.
3. That, considering the conflict between the provisions of the Sate Notification i.e. The Uttarakhand Special Provisions for Urban Local Bodies and Authorities Act, 2018 as amended on 24.09.2021 with the

notification of the Ministry of Jal Shakti, Government of India issued on dated 07.10.2016, it was decided that legal advice from the State Law Department be sought.

4. That, the District Magistrate, Dehradun vide its letter dated 20.11.2023 sought advice from the Law Department in the instant matter. Copies of letters dated 20.11.2023 & 03.02.2024 is enclosed as **Annexure-2**. Reply is awaited.
5. That, it is pertinent to mention that 177 drains of Rispana nadi has been tapped through construction of 144 nos. interception & diversion (I&D). Moreover, about 76% *basins* of *Rispana nadi* basin has been connected with sewerage network and rest of work is under process. In this regard, reply of Uttarakhand Peyjal Nigam is enclosed as **Annexure-3**.
6. That the performance monitoring of Sewage Treatment Plants (STPs) located in the *Rispana nadi* basin is being carried out by the Uttarakhand Pollution Control Board on monthly basis. Monitoring data is being shared with concerned department /agency as well as uploaded in web site of UKPCB and available at : [https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/184-sewage-treatment-plant-\(stp\)](https://ueppcb.uk.gov.in/pages/display/184-sewage-treatment-plant-(stp))

\*\*\*\*\*



मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-

1. श्री धनंजय मोहन, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
2. श्री आर.के.मिश्र, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
3. श्री धर्म सिंह मीणा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनय भार्गव, वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड।
5. श्री राजीव धीमान, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. श्री मनुज गोयल, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री नितीशमणी त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. श्री वैभव कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
9. श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री रामजी एस.शर्मा, अपर जिलाधिकारी, देहरादून।
11. श्री अशोक पाण्डे, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
12. श्री अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। अपर सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम भारत संघ व अन्य वादी द्वारा जनपद-देहरादून के रिस्पना नदी के सूखे तल पर अनाधिकृत रूप से झुगियाँ बनाने और अनुपचारित घरेलू सीवेज, डेयरी अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में दायर किया गया है।

2 - प्रश्नगत प्रकरण में मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्शोपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

(1) मा.हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-16 के क्रम में जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 एवं उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 में टकराव/विरोधाभाष होने के दृष्टिगत प्रकरण

पर न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय।

(कार्यवाही-शहरी विकास विभाग/पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन)

(2) प्रश्नगत प्रकरण में यथाशीघ्र मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर ली जाय। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोडल) द्वारा संबंधित विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए, सूचना प्राप्त कर, एक सूक्ष्म पी.पी.टी. तैयार कर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तुत किया जाय। उक्त बैठक में पेयजल विभाग को आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही-MS,UKPCB)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये प्रदत्त निर्देशों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही के साथ बैठक का समापन किया गया।

Signed by Dharm Singh  
Meena

Date: 30-08-2023 18:03:48

(धर्म सिंह मीणा)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

संख्या- /XXXVIII-1-2023

देहरादून: दिनांक:- अगस्त, 2023

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, सिंचाई विभाग/शहरी विकास विभाग/पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून।

आज्ञा से,

Signed by Ashutosh Shukla

Date: 30-08-2023 18:17:43

(आशुतोष शुक्ल)

उप सचिव।

प्रेषक,

Annexure-2

जिलाधिकारी,  
देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
विधि एवं न्याय,  
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संख्या 537/एल0बी0सी0-2024

दिनांक 03 फरवरी, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-  
417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश  
दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-416/एल0बी0सी0-2023 दिनांक 20.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या-15,16 व 17 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किये जाने कि अपेक्षा की गई थी। किन्तु शासन से उक्त मार्गदर्शन आतिथि तक अपेक्षित है।

अतः शासन से पुनः अनुरोध है, कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्या-15,16 व 17 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। ताकि नियत तिथि दिनांक 06.02.2024 से पूर्व अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,

  
(सोनिका)  
जिलाधिकारी  
देहरादून।

प्रतिलिपि:- श्री राहुल वर्मा, अपर महाधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 01.02.2024 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है, जो कि अपेक्षित है। यथास्थिति से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

02:- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
जिलाधिकारी  
देहरादून।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
विधि एवं न्याय,  
उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संख्या 416

/एल0बी0सी0-2023

दिनांक 20 नवम्बर, 2023

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर संख्या-15,16 व 17 में निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

15:- In its reply filed by the Municipal Corporation, it has been submitted that demarcation of the flood plain zone of the river and tapping discharge of untreated sewage in the river falls within the ambit of Irrigation Department, Dehradun and Payjal Nigam, Uttarakhand. These departments are directed to take action for demarcating the land and to identify and to protect. It has further been submitted that vide notification dated 26.07.2018, the special provision for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 under Section 4 (2) and 4 (3) have been amended and directions have been issued to maintain status quo and no punitive action can be taken against the encroachers established alongside the river Rispana till the year 2024.

16:- The state notification conflicts with the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation notification dated 07.10.2016 under which section 42 provides as follows;

**42. Giving of prior approval in certain matters:**

- (a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga.
- (b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area.
- (c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat.
- (d) construction of jetties.
- (e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries.
- (f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco- sensitive areas.
- (g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

कमांश-02



17. Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MOEF & CC.

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।  
संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,



(सोनिका)

जिलाधिकारी

देहरादून।



प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



जिलाधिकारी

देहरादून।



8  
21/11/23

Item No. 04

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**(Through Video Conference)**

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand &amp; Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 25.07.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: None  
Respondent: Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand  
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB  
Mr. Aman Rab, Adv. for MC, Dehradun

**ORDER**

1. The issue raised in this application is unauthorized raising of jhuggis on the dry river bed of river Rispana in Dehradun. The quality of water in all the four rivers has deteriorated because of domestic sewage, dairy waste and untreated industrial effluent being discharged into them. These rivers in turn discharge their pollution load in river Ganga at Haridwar. The number of jhuggis increase each year specially since municipal facilities are now available to them. Natural calamity in which overflowing river Rispana created havoc and washed away several habitations with loss of lives have occurred in Dehradun since 2013. Despite these happenings, persons are allowed to build jhuggis in the sensitive area of river bed knowing fully well that a catastrophe may be lurking.
2. According to the provisions of Article 21 read with article 48 (A) of the directive principles of State Policy, Right to Life includes right to have fresh air and healthy environment. Nobody has the right to create pollution

endangering the life of others on the grounds of commercial activities. This universe and living beings are creation of almighty called Bhagwan which means and includes "Chiti, Jal, Pawak, Gagan, Sameera, Panch Rachit Yah Adham Sareera". These five words signify five elements of life:-

*Bha = Bhumi*

*Ga = Gagan*

*Wa = Vau*

*Aa = Agni*

*Na = Neer*

3. When natural cycle of all five is disturbed due to mixing of poisonous or harmful material, it is nature of pollution. We are living in the age of technology where people use latest machines and other technological products to get our work done. We move from one place to another using modern transport system based on bikes, cars, buses, jeeps and trucks. We use air conditioners in our homes, offices and vehicles to maintain their temperature to desired level. Pollution is a situation when something is added to the natural environment which is not naturally there; natural environment is comprised of air, land and water. So any contamination in any of the element of environment will be regarded as pollution; however, nature of contamination is quite different in each component and may take many forms, land pollution, air pollution and water pollution.
4. Water pollution is a relatively new phenomenon, and one can safely utter that it is solely the result of industrial waste and sewage waste which is thrown into the rivers and oceans. However, there is significant contribution of our poor sewerage system to it. It has stuffed up marine life. Admittedly, it doesn't affect us in the short run but it does affect in the long run. We have seen societies suffering from water diseases because they have consumed filthy water. It cannot be disputed that no development is possible without some adverse effect on the ecology and environment, and the projects of public utility cannot be abandoned and it is necessary to adjust the interest of the people as well as the necessity to maintain the

environment. A balance has to be struck between the two interests. Where the commercial venture or enterprise would bring in results which are far more useful for the people, difficulty of a small number of people has to be bypassed. The comparative hardships have to be balanced and the convenience and benefit to a larger section of the people has to get primacy over comparatively lesser hardship. This indicates that while applying the concept of "sustainable development" one has to keep in mind the "principle of proportionality" based on the concept of balance. It is an exercise in which we have to balance the priorities of development on one hand and environmental protection on the other hand.

5. Grievance of the applicant is that due to increase in population, enormous, unregulated and unplanned construction have been done on both sides of River, which is continuous and increasing rapidly. Illegal construction was done on huge scale on banks of river. In some places illegal colonies were developed by the local land mafia encroaching the bank of river causing enormous pollution and disturbing the natural steams of the river.
6. Section 3 of this The Environment (Protection) Act, 1986 Confers power on the Central Government to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution. 'Environment' includes water, air and land and the inter-relationship which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, micro-organism and property. (Vide section 2(a) of the Environment (Protection) Act, 1986).
7. Section 2 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 defines the word -
  - (j) "stream" which includes-
    - i. River;
    - ii. Water course (whether flowing or for the time being dry);
    - iii. Inland water (whether natural or artificial)

- iv. sub-terranean waters;
- v. sea or tidal waters to such extent or, as the case may be, to such point as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf;

(e) "Pollution " means such contamination of water or such alteration of the physical, chemical or biological properties of water or such discharge of any sewage or trade effluent or of any other liquid, gaseous or solid substance into water (whether directly or indirectly) as may, or is likely to, create a nuisance or render such water harmful or injurious to public health or safety, or to domestic, commercial, industrial, agricultural or other legitimate uses, or to the life and health of animals or plants or of aquatic organisms but the state Government as well as State pollution control board and state Forest department have not taken any action to check Pollution, while they are statutory obliged to do so.

8. It is argued by the learned counsel for the applicant that Hon'ble Supreme Court of India in the case "Friends Colony Development Committee vs. State of Orissa and Other [(2004) 8 SSC 7331] observed as follows :-

*"In all developed and developing countries there is emphasis on planned development of cities which sought to, be achieved by zoning, planning and regulating building construction activity. Such planning, though highly complex is a matter based on scientific research, study and experience leading to rationalization of laws by way of legislative enactments and rules and regulations framed there under. Zoning and planning do result in hardship to individual property owners as their freedom to use their property in the way they like, is subjected to regulation and control. The private owners are to some extent prevented from making the most profitable use of their property. But for this reason alone the controlling regulations cannot be termed as arbitrary or unreasonable. The private interest stands subordinated to the public good. It can be stated in a way that power to plan development of city and to regulate the building activity therein flows from the police power of the State. The exercise of such governmental power is justified on account of it being reasonably necessary for the public health, safety morals or general*

*welfare and ecological considerations; though unnecessary or unreasonable intermeddling with the private ownership of the property may not be justified.)”*

9. It is further submitted that illegal constructions/encroachments upon riverbeds/banks, hills in the form causing harm to the environment of the river polluting natural water and danger for water bodies, defacing the beauty of the River and damage to the environment of the River, hills and the heritage sites of is irreversible and permanent. For that constructions of concrete buildings, cutting of trees near river sites and blowing up of the hills for vested interests will be a great loss to nature and environment. It is further argued that the water is the most essential requirement to sustain the human life and, therefore, there is need to preserve and protect it. The sources from which water is available is well known. Each source carries along with it special characteristics and bio-diversity which sustains the source. The courts are under obligation to see the protection and preservation of these water resources and Prevention of its contamination.

***Given the responsibility vested in municipalities under Article 243-W of the Constitution, as also, in Item 6 of Schedule XII, wherein the aforesaid obligation, pointedly extends to “public health, sanitation conservancy and solid waste management”, we are of the view that the onus to operate the existing common effluent treatment plants, rests on municipalities (and/or local bodies). Given the aforesaid responsibility, the municipalities (and/or local bodies) concerned, cannot be permitted to shy away from discharging this onerous duty. In case there are further financial constraints, the remedy lies in Articles 243-X and 243-Y of the Constitution. It will be open to the municipalities (and/or local bodies) concerned, to evolve norms to recover funds, for the purpose of generating finances to install and run all the “common effluent treatment plants”, within the purview of the***



*between the banks occupied by the river at its fullest flow.*

12. Floodplain zoning has been accepted as an important nonstructural strategy for flood management. The basic concept of floodplain zoning is to regulate land use of floodplains to restrict damage caused due to floods. The floodplain zoning, therefore, aims at determination of locations so that flood damages are reduced to minimum. A very restrictive activity can be allowed in that area. It is not only to protect the areas from damage resulting from floods and failure of water protective measures, but is also useful in reducing the damage caused due to drainage congestion, particularly in urban areas. The Commission claims to have prepared a model bill relating to flood plain zoning. This model bill provides for different categories based of priorities in f flood plain. The floodplain must be demarcated, kept free from any permanent developments and wherever it is possible, it should be restored to its original position.

13. Thus, it is necessary to call upon the authorities to demarcate the floodplain for the flood of once in 25 years and to prohibit any kind of development activity in the area in question. Furthermore, the Committee should consider restoration of the area and wherever necessary, even demolish the properties, which are likely to be dangerously exposed to the flood and are even affecting the ecology and bio-diversity and flow of the river.

14. Being an integral part of the river, floodplain of the river requires protection. Floodplains play significant role in maintaining the bio-diversity and aquatic life of the river. It's significance cannot be overlooked, in terms of environment and ecology. There are numerous dimensions involved while identifying the floodplains. It is required to

categorize it into different zones, namely, No Development Zone, Regulated Zone and a Free Zone for development. The principle of Sustainable Development itself justifies the classification of floodplains into such zones for protecting the river. This Tribunal in the case of Manoj Misra (supra) had the occasion to deal with the concept of floodplain, its zoning and management.

15. In its reply filed by the Municipal Corporation, it has been submitted that demarcation of the flood plain zone of the river and tapping discharge of untreated sewage in the river falls within the ambit of Irrigation Department, Dehradun and Payjal Nigam, Uttarakhand. These departments are directed to take action for demarcating the land and to identify and to protect. It has further been submitted that vide notification dated 26.07.20218, the special provision for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 under Section 4 (2) and 4 (3) have been amended and directions have been issued to maintain status quo and no punitive action can be taken against the encroachers established alongside the river Rispana till the year 2024.

16. The state notification conflicts with the notification issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation notification dated 07.10.2016 under which section 42 provides as follows;

**42. Giving of prior approval in certain matters:**

- (a) *engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga;*
- (b) *construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;*
- (c) *construction of Ghats or extension of any existing Ghat;*
- (d) *construction of jetties;*

construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries;

(f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco-sensitive areas;

(g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

17. Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MoEF & CC.

18. Accordingly, we direct the Secretary, Environment, Uttarakhand to re-examine the matter and to take appropriate action. We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/ river body and to ensure the compliances of the environmental act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks.

**List it on 17.10.2023**

Sheo Kumar Singh, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 25, 2023  
O.A No. 417/2022  
PU



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 264/XXXVI (3)/2021/55(1)/2021

देहरादून, 24 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021’ पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 24 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 सितम्बर, 2021 ई0 (आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन)  
अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् रूप में यह अधिनियमित हो-

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।  
(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर होगा।  
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का  
संशोधन

2. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 में "03 वर्ष" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "06 वर्ष" शब्द और अंक रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,  
प्रमुख सचिव।

VI-1 NR-1  
उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 सितम्बर, 2021 ई0 (आश्विन 02, 1943 शक)

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित संशोधन किये जाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021' को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

बंशीधर भगत  
मंत्री।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित.

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 ई०

श्रावण 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 273/XXXVI(3)/2018/53(1)/2018

देहरादून, 26 जुलाई, 2018

### अधिसूचना

### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन श्री राज्यपाल ने “उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018” पर दिनांक 26 जुलाई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 02, वर्ष- 2018 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान)

अध्यादेश, 2018

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-02, वर्ष 2018)

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड में अनधिकृत विकास, अतिक्रमण और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अध्यादेश

चूँकि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

अध्याय-एक  
प्रारम्भिकसंक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों/ प्राधिकरणों पर लागू होगा।।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्यादेश में:-

(क) "अतिक्रमण" से नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक/राजकीय भूमि, सड़क मार्ग, गलियों, पैदल मार्गों आदि में आवासीय, व्यावसायिक अथवा अन्य कार्यों हेतु किये गये अतिक्रमण एवं अस्थायी, अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी निर्माण अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र में लागू मारुटर प्लान / योजना का उल्लंघन कर किया गया हो;

(ख) "अध्यादेश" से "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018" अभिप्रेत है;

(ग) "नगर निकाय" से ऐसी स्वायत्तशासी संस्था अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित व अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत गठित है, और इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत शामिल हैं;

(घ) "दण्डात्मक कार्यवाही" से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन अनधिकृत विकास के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अभिप्रेत है जिसमें ध्वस्तीकरण, परिसर की सीलिंग तथा व्यक्तियों अथवा उमके व्यवसाय का विद्यमान स्थात से विस्थापन न्यायालय अथवा अन्यथा के अनुपालन में किया गया हो;

4

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 26 जुलाई, 2018 ई0 (श्रावण 04, 1940 शक सम्बत्)

इस अध्यादेश के प्राविधानों का कतिपय प्रकरणों पर लागू न होना

5. इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणी के अनाधिकृत विकास के लिए धारा 4 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।-
- (1) दिनांक 11.03.2016 के पश्चात प्रारम्भ किये गये और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्य।
- (2) सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।
- (3) सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/विकास।

राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

6. राज्य सरकार, समय-समय पर स्थानीय नगर निकायों एवं प्राधिकरणों को, जैसा कि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेंगी। नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निर्गत निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय- तीन  
प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7. इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

8. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

9. यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

डॉ० कृष्ण कान्त पाल,  
राज्यपाल,  
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,  
मीना तिवारी,  
प्रमुख सचिव।

(ड.) "नियमावली" से "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) नियमावली, 2018" अभिप्रेत है, किन्तु इस अध्यादेश के अधीन नियमावली का प्रख्यापन से पूर्व तक "उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्धारण, पुनर्व्यवस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016" प्रचलन में रहेगी;

(च) "मलिन बस्ती" से नगर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहाँ अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौगिक अधिकारों के अभाव के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो। इनमें ऐसी बस्तियाँ भी सम्मिलित होंगी जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित की गयी हों;

(छ) "अनधिकृत विकास" से ऐसे भू-उपयोग अथवा भवन उपयोग तथा भवन निर्माण अभिप्रेत है जो स्वीकृत प्लान से सुसंगत न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान अथवा ले-आऊट प्लान अथवा जैसा भी प्रकरण हो, का उल्लंघन करता हो तथा इसके अंतर्गत अतिक्रमण भी शामिल है।

अध्यादेश का  
अध्यारोही प्रभाव

3. इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अध्यादेश से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

#### अध्याय- दो

राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही व निर्देश देने की शक्ति

प्रवर्तन को स्थगित  
रखा जाना

4. (1) इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के तिथि से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास कर सकेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके।
- (2) उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।
- (3) उपधारा (1) में संतर्भित अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली किसी दण्डात्मक कार्यवाही को इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

**RAHUL VERMA**  
 Advocate [LL.M.]  
 Supreme Court of India  
 Additional Advocate General  
 State of Uttarakhand for  
 Supreme Court of India & for  
 National Green Tribunal

137, Tower No.10,  
 SUPREME ENCLAVE,  
 MAYUR VIHAR PHASE-I,  
 Delhi-110091  
 (Mobile): 09717706032  
 Email  
[advrahulverma9999@gmail.com](mailto:advrahulverma9999@gmail.com)

**MOST URGENT**  
**Through e-mail**

DATED:-01.02.2024

To,  
 The Principal Secretary, Department of Environment & Forest, Govt. of Uttarakhand,  
 Secretariat, 4, Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand

Sub: For ensuring the compliance of directions passed by Hon'ble National Green Tribunal, vide its order dated 25.07.2023 & 17.10.2023

In Re: O.A. No. 417 of 2022 -Niranjan Bagchi -Vs- State of Uttarakhand  
 (Pending before the Hon'ble National Green Tribunal)

Respected Sir,

That the averment of applicant is that the applicant is resident of Dehradun, Uttarakhand and sent a letter to the Hon'ble National Green Tribunal, which has been treated and registered as abovementioned Original Application, through the abovementioned letter petition, the applicant raised his grievance that unauthorized raising of jhuggis on the dry river bed of river Rispana in Dehradun. The applicant further submitted that river Rispana is one of the four main rivers in Dehradun. The quality of water in all the four rivers has deteriorated because of domestic sewage, dairy waste and untreated industrial effluent being discharged into them. Applicant further raised his grievance that these rivers in turn discharge their pollution load in river Ganga at Haridwar. The number of jhuggis increase each year specially since municipal facilities are now available to them. Natural calamity in which overflowing river Rispana created havoc and washed away several habitations with loss of lives have occurred in Dehradun since 2013. Applicant further submitted that despite these happenings, persons are allowed to build jhuggis in the sensitive area of river bed knowing fully well that a catastrophe may be lurking.

That I have already sent the letter dated 27.07.2023, the directions of the Hon'ble National Green Tribunal stated below, which were directed to be complied are as follows:-

.....  
 17. Considering the above facts, the state of Uttarakhand, Pollution Control Board and Collector are directed to submit its report as applicability of the notification which is in contravention of notification dated 07.10.2016 (SO3187 (E), MoEF & CC. 18. Accordingly, we direct the Secretary, Environment, Uttarakhand to re-examine the matter and to take appropriate action.

We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/ river body and to ensure the compliances of the environmental act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks.

List it on 17.10.2023."

..2/-

321  
 01-02-24

V. P. Singh  
 LBC/DSC  
 P. Singh  
 ADMCFIR  
 01/02/24

**RAHUL VERMA**  
 ADVOCATE [LL.M.]  
 SUPREME COURT OF INDIA  
 Additional Advocate General  
 for State of Uttarakhand for  
 Supreme Court of India

OFFICE-  
 137, Tower No.10,  
 SUPREME ENCLAVE,  
 MAYUR VIHAR PHASE-I,  
 Delhi-110091  
 (Mobile): 09717706032  
 Email [advrahulverma9999@gmail.com](mailto:advrahulverma9999@gmail.com)

//2//

That the matter was listed on 17.10.2023 before the Hon'ble Tribunal, after hearing at length, I humbly requested the Hon'ble Tribunal to grant time to place on record Action Taken Report, the Hon'ble Tribunal was pleased to direct to clear the illegal encroachments, while giving the following directions:-

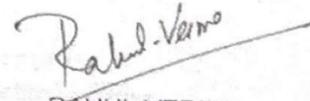
"1. Mr. Rahul Verma, Addl. Advocate General for respondents no. 1, 2 and 5 seeks time for filing of Action Taken Report in compliance of orders passed by this Tribunal.

2. Action Taken Report be filed by respondents no. 1, 2 and 5 within three months by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF/Word file.

The matter is coming for hearing on coming Monday and the Action Taken Report has to be filed before the Hon'ble National Green Tribunal till Saturday.

In the abovementioned circumstances, it is requested to direct the concerned officials to ensure the compliance of the directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal to avoid any adverse order against the State.

Regards,

  
 RAHUL VERMA

Copy to:  
 The District Magistrate, Dehradun, Collectorate, Nardev Shastri Marg, Race Course, Dehradun, Uttarakhand.

Item No.04

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)  
Original Application No.417/2022

Niranjan Bagchi

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand

...Respondents

Date of hearing: 17.10.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None.

Respondents: Mr. Rahul Verma, Addl. Advocate General and Mr. Kaushal Gautam, Advocate for respondents no. 1, 2 and 5 (through VC).  
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondents no. 3 (through VC).  
Mr. Aman Rab, Advocate for respondent no. 4- Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun (through VC).

**Application is registered based on a letter Petition received by Post.**

**ORDER**

1. Mr. Rahul Verma, Addl. Advocate General for respondents no. 1, 2 and 5 seeks time for filing of Action Taken Report in compliance of orders passed by this Tribunal.

2. Action Taken Report be filed by respondents no. 1, 2 and 5 **within three months** by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF/Word file.

O. A. No. 417/2022

Niranjana Bagchi Vs. State of Uttarakhand  
-2-

3. List the matter for further consideration on 06.02.2024.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 17<sup>th</sup>, 2023  
AG



कार्यालय – 0135-2678078  
0135-2672404

113

Annexure-3

फैक्स : 0135-2672337  
ई-मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम  
प्रधान कार्यालय 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक.....684.....

नागर क्रु० / N.G.T. / 36

दिनांक 25-10-23

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"  
46 बी, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़  
देहरादून।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0-183-586/2023/826 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध चाही गयी आख्या सम्बन्धित से प्राप्त कर आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रहस्य - उत्तराखण्ड

भवदीय

  
25-10-23  
(जी0पी0 सिंह)

महाप्रबन्धक,

(बा0स0कार्य0/जे0जे0एम0 अर्बन)



## उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा,

गली नं० 11, राजेन्द्र नगर, देहरादून -248001

पत्रांक : 2809 / 374 / 15 दिनांक : 19-10-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (नागर),  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

विषय :- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पृ०सं० 626/नागर अनु०/N.G.T/34 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन सं० 417/2022 के अनुपालन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चाही गई आख्या/अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
01	No. of drains and their tapping status.	रिस्पना नदी के दोनो ओर वर्तमान तक 144 आई० एण्ड डी० का निर्माण कर 177 नालियों को टैप कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं आई० एण्ड डी० के संचालन एवं रखखाव का कार्य मै० ई०एम०एस० इन्फ्राकॉन प्रा०लि० द्वारा किया जा रहा है।
02	Status of sewerage network and connected STPs with their utilization.	रिस्पना बेसिन की लगभग 76 प्रतिशत बस्तियों को सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित किया जा चुका है एवं शेष क्षेत्र को भी लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। रिस्पना बेसिन के अवशेष क्षेत्रों हेतु पूर्व में प्राक्कलन गठित कर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसे एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली द्वारा पुनः संशोधित कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं जिस पर कार्यवाही गतिमान है। संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धनावंटन उपरान्त ही सीवर लाईन बिछाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

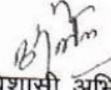
भवदीया

  
(भारती रावत)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अधिशासी अभियन्ता  
(am)

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के अनुपालन में प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नलिखित विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आख्या/सूचना अपेक्षित है:-

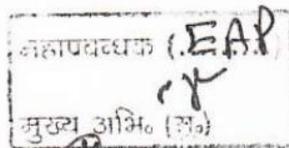
1. Nagar Nigam, Dehradun
  - i) Survey of identifying encroachment.
  - ii) Appropriate Action taken for removal of the encroachment.
2. Uttarakhand Peyjal Nigam, Dehradun
  - i) Nos. of drains and their tapping status.
  - ii) Status of sewerage network and connected STPs with their Utilization.
3. Irrigation Department:
  - i) Status of Flood Plain Zonation of Rispana River.

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित बिन्दुओं पर अद्यतन आख्या/सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। आख्या/सूचना की प्रति ई-मेल (rskathait2009@gmail.com)द्वारा भी प्रेषित करने का कष्ट करें। शुभ सन्दर्भ हेतु बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:-यथोपरि।

G.M (CEAP) / CE (M)

M.D  
29/9



भवदीय

(एस0 के0 पटनायक)  
सदस्य सचिव

Vigent  
BB (Nagar)  
Lyander  
29/9